संघ के तत्वावधान में हजारों शिक्षकों ने चट्टोपाध्याय आयोग की सिफारिशों को फौरन लागू करवाने की मांग पर बल देने के लिए बोट-क्लब पर धरना दिया था ।

(ख) यदि हां, तो शिक्षकों की अन्य मांगे क्या-क्या हैं और चट्टोपाध्याय आयोग की सिफारिशों को कब तक लागू कर दिए जाने की संभावना है ; और

(ग) इन मांगों पर सरकारी सहमति के बावजूद इनके कार्यान्वयन में क्या-क्या कठिनाईयां है और इन्हे कब तक दूर कर दिए जाने की संभावना है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एल० पी० साहो) : (क) और (ख) अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने 15-11-88 को बोट क्लब लान में धरना दिया था । अखिल भारतीय प्राइमरी शिक्षक संघ की मुख्य मांगे राष्ट्रीय शिक्षक आयोग-1 द्वारा यथा अनुसंशित देश में प्राइमरी-स्कूल के अध्यापकों के वेतनमानों में संशोधन करना, राज्य में महंगाई भत्ता, केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के बराबर करना तथा राष्ट्रीय शिक्षक आयोग-1 द्वारा यथा अनुसंशित चिकित्सा सुविधाएं, गृह निर्माण अग्रिम राशि आदि हैं ।

(ग) राष्ट्रीय शिक्षक आयोग-1, चतुर्थ वेतन आयोग और राष्ट्रीय-शिक्षा नीति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए, सरकार द्वारा संघ शासित क्षेत्रों के वेतनमान संशोधित कर दिए गए है । सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षक आयोग-1 द्वारा यथा-अनुसंशित अध्यापकों के लिए सतत रूप से चलने वाली वेतनमानों की संकल्पना को स्वीकार नही किया है । राज्य में कार्यरत अध्यापकों के लिए सरकार का यह दृष्टिकोण है कि वेतनमानों और संबंधित सेवा शर्तों का समय-समय पर संशोधन करने के लिए राज्य सरकारों का अपना तंत्र है । राज्य सरकारों के अध्यापकों के लिए लागू वेतनमानों में उचित रूप से संशोधन करना संबंधित राज्य सरकारों का काम है ।

Holding of Rallies by AIKVTA

‡*868. SHRI MOSTAFA BIN QUASEM:
SHRI ASHOK NATH VERMA:

Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that All India Kendriya Vidyalaya Teachers Association had held rallies in major cities in the country on 21st November and submitted a memorandum to him in New Delhi to press their demands;

(b) if so, what are the main demands of the said Association; and

(c) what is Government's reaction to each of these demands?

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI P. SHIV SHANKER): (a) to (c) A Memorandum dated 21.11.1988 was submitted to the Minister of Human Resource Development by the All India Kendriya Vidyalaya Teachers' Association. Their main demands are (i) immediate implementation of the Chattopadhyaya Commission's recommendations including revision of pay-scales (ii) opposition to Hospitals and other Institutions Bill (iii) issues relating to the working of Kendriya Vidyalaya Sangathan.

Keeping in view the recommendations of the NCT-I, the Fourth Central Pay Commission and provisions of National Policy on Education, the pay-scales for teachers in the Union Territories and Government of India's autonomous bodies have been revised by the Government on 12.8.1987. The Government has not accepted the concept of a running pay-scale for teachers as recommended by the Chattopadhyaya Commission.

Joint Consultative Machinery for the Kendriya Vidyalaya Sangathan has been set up which provides the forum

‡*361 and *368 were taken together.

ror consultation between the Association and the Kendriya Vidyalaya Sangathan. The Association can appropriately discuss all its demands concerning the management of Kendriya Vidyalaya Sangathan in the Joint Consultative Machinery.

श्री ईश दत्त यादव : माननीय सभापति जी, माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री जी का जो उत्तर है वह पूर्णतया निराशाजनक है और सरकार की जो गलत शिक्षा नीति है उसका द्योतक है । सरकार की कोई रुचि मालूम नहीं पड़ती शिक्षा के प्रचार और प्रसार में । यही कारण है कि आज देश की दो तिहाई से अधिक जनसंख्या जो है वह अशिक्षित है । किसी भी प्रजातांत्रिक देश में अशिक्षा, गरीबी, बेकारी और बीमारी ये चार शत्रु होते हैं और इसमें अशिक्षा जो है वह सबसे बड़ा शत्रु है । देश की एकता, राष्ट्रीयता और जनतंत्र को समाप्त करने वाली अशिक्षा होती है । प्रदेशों के जो प्राथमिक शिक्षक संघ हैं, पूरे देश के प्रदेशों के, जो राष्ट्र के निर्माता हैं, जो छोटे बच्चों के जीवन को सुधारने वाले हैं, उन लोगों ने विभिन्न प्रदेशों में अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया कि पूरे देश में समान शिक्षा नीति लागू की जाय और समान वेतन का सिद्धांत लागू किया जाय लेकिन प्रदेश सरकारों ने कोई सुनवाई नहीं की । मान्यवर, दो वर्ष पहले उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक संघ

श्री सभापति : प्रश्न पूछिए ।

श्री ईश दत्त यादव : मैं प्रश्न पूछ रहा हूं । उत्तर प्रदेश में जो प्राथमिक शिक्षक संघ और कर्मचारी संघ के लोग अपनी मांगों को लेकर लखनऊ में जब प्रदर्शन कर रहे थे तो वहां की सरकार ने उनके ऊपर डंडे चलवाये, लाठियां चलवाई और गोलीबारी की जिसमें बहुत से लोग घायल हो गए । अन्त में विवश होकर

श्री सभापति : प्रश्न कीजिए । मैं आपको ज्यादा टाइम नहीं दूंगा । भूमिका इतनी बड़ी मत बांधिए ।

श्री ईश दत्त यादव : मैं प्रश्न कर रहा हूं ।

अपनी मांगों को लेकर पूरे देश के शिक्षक संघ के लोगों ने बोट क्लब पर धरना दिया और सरकार को मांग पत्र दिया और चट्टोपाध्याय कमीशन, जिसको केन्द्रीय सरकार ने नियुक्त किया था उसने संस्तुति दी . . .

श्री सभापति : आपके प्रश्न में यह लिखा हुआ है ।

श्री ईश दत्त यादव : मैं प्रश्न पूछ रहा हूं कि क्या केन्द्रीय सरकार प्रदेश सरकारों को यह निर्देश देगी कि वे चट्टोपाध्याय कमीशन की संस्तुतियों को लागू करें और क्या केन्द्रीय सरकार इसके लिए प्रदेश सरकारों को पर्याप्त धनराशि आवंटित करेगी ?

श्री एल पी० साही : सभापति महोदय, भारत सरकार इस मामले में निर्देश तो राज्य सरकारों को नहीं देती आई है और आदेश देने का सवाल भी नहीं उठता । जहां तक अपने फण्ड से उसको पूरा करने का सवाल है उसमें अभी भारत सरकार अपने को समर्थ नहीं पाती है । इसलिए यह प्रश्न नहीं उठता है ।

श्री ईश दत्त यादव : मान्यवर, केन्द्रीय विद्यालय जो केन्द्रीय सरकार के अधीन हैं केन्द्रीय विद्यालयों में भी प्राथमिक शिक्षक संघ हैं । उन्होंने भी 21-11-88 को पूरे देश में प्रदर्शन किया और एक मांग-पत्र भारत सरकार को दिया । मैं यह जानना चाहता हूं कि जो अध्यापक आपके मातहत हैं उनके वेतनमान को आप संशोधित करेंगे और दूसरा इसी प्रश्न के साथ में यह कहना चाहता हूं कि चट्टोपाध्याय कमीशन ने यह भी संस्तुति की थी कि पूरे देश में 70 प्रतिशत शिक्षा एक समान होनी चाहिये और 30 प्रतिशत प्रदेशों की स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार होनी चाहिये । क्या सरकार केन्द्रीय विद्यालयों को प्राथमिक शिक्षकों को यह संशोधित वेतनमान जो चट्टोपाध्याय कमीशन के अनुसार है वह देगी और 70 फीसदी देश की शिक्षा को एक समान बनाने की व्यवस्था करेगी ?

श्री एल०पी०साही : यह भी केन्द्रीय विद्यालय का सवाल है और एक दूसरा प्रश्न भी आज ही रखा गया है, अगर आपकी इजाजत हो तो . . .

श्री सभापति : वह मैंने क्लब कर दिया है।

श्री एल०पी०साही : जहां तक केन्द्रीय विद्यालयों का सवाल है उनमें तीन तरह के शिक्षक हैं । एक प्राइमरी टीचर कहलाते हैं, दूसरे ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर है और तीसरे पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हैं । तीनों की क्वालीफिकेशन भी भिन्न है । तीनों के अलग अलग वेतन स्तर है और उसमें इधर सुधार किया गया है । जो चट्टोपाध्याय कमीशन की रिपोर्ट हुई उस पर सरकार ने विचार किया है । वस्तुतः चट्टोपाध्याय कमीशन और फोर्थ पे रिविजन कमीशन दोनों इसको देख रहे थे । चटटोपाध्याय कमीशन के टर्म्स आफ रेफ़ेंस में यह पे स्केल था नहीं लेकिन इलस्ट्रेशन के तौर पर उन्होंने एक जगह कहा है अच्छा होता कि इस तरह 500 से लेकर 3900 के वेतनमान में शिक्षक रहते और धीरे-धीरे पदोन्नति पा कर डी०पी०आई० तक पहुंच जायें तो अच्छा है लेकिन खुद चटटोपाध्याय कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि विभिन्न राज्यों में विभिन्न स्तर के पे स्केल हैं वह हिस्टोरीकल चीज है जो अलग-अलग राज्यों के पे स्केल बनते रहे हैं इसलिए इनको एक जगह लाया जाए तो बहुत अच्छा है लेकिन इसमें समय लगेगा इसकी कल्पना चटटोपाध्याय कमीशन ने खुद की है।

श्री सभापति : तो वह समय आप लगा रहे हैं।

श्री एल०पी० साही : जी नहीं । उसके बाद भारत सरकार ने उस पर विचार किया और नया पे स्केल 12-12-87 को लागू किया जो 1-1-86 से लागू हो गया । चट्टोपाध्याय कमीशन ने कहा था कि प्राइमरी शिक्षकों को डेढ़ सौ रुपया टीचिंग अलाउंस मिलना चाहिये और सौ रुपये . . .

श्री सभापति : वह दे रहे हैं आप ?

श्री एल०पी० साही : वह दे रहे हैं हुजूर । इनको मालूम नहीं है ।

श्री सभापति : श्री रामनरेश यादव (व्यवधान)

श्री राम नरेश यादव : मान्यवर, मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है उससे एक बात स्पष्ट हो रही है कि यह जो डी०पी० चट्टोपाध्याय जी ने जब उस समय के शिक्षा मंत्री को 25-3-88 को रिपोर्ट प्रस्तुत की थी प्रस्तुत करते समय एक पत्र भी उनको लिखा गया था वह मैं आपको पढ़ कर सुना रहा हूं ।

श्री सभापति: पत्र बहुत बड़ा है क्या ?

श्री राम नरेश यादव : सिर्फ चार लाइन में पढ़ रहा हूं । उन्होंने लिखा था प्रारम्भिक शिक्षा सर्वव्यापी बनाए जाने की आवश्यकता है । सरकार की नयी शिक्षा नीति में हमारे राष्ट्रीय लक्ष्य को न केवल उचित स्थान मिलना चाहिये।". . . बल्कि इसके लिए पर्याप्त वित्तीय साधनों की व्यवस्था भी की जानी चाहिये । यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो नयी प्रणाली बिल्कुल विफल हो जाएगी ।" । यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो प्राथमिक शिक्षा का सार्वजनीकरण करने की योजना है, नयी शिक्षा नीति के तहत, इस बयान से स्पष्ट है कि सरकार वास्तविक रूप से प्राथमिक शिक्षा का सार्वजनीकरण नहीं करना चाहती है, इसीलिए जो संस्तुतियां हैं उन संस्तुतियों को जानबूझकर नहीं लागू करना चाहती है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार जो अनुशंसाएं हैं उन अनुशंसाओं को सिद्धांत रूप में सही मानती हैं, जैसे कि महंगाई भत्ता केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के बराबर करना, फिर उनके गृह निर्माण की समस्या आदि अन्य जो सारी चीजें हैं । क्या नीतितः सरकार इनको मानती हैं और अगर मानती हैं तो मानकर जितने वेतनमान हैं उन वेतनमानों

पर कोई राष्ट्रीय नीति सरकार निर्धारित करने का कष्ट करेगी, विचार करेगी, क्योंकि आखिर प्रश्न तो इसलिए ही उपस्थित हो रहा है । आप नयी शिक्षा नीति लागू कर रहे हैं लेकिन नये वेतनमानों में एक वेतन-मान भी लागू करने पर विचार नहीं कर रहे हैं । क्या इस संदर्भ में आप इन सारे प्रश्नों का उत्तर देते हुये विचार करेंगे कि सारे प्राथमिक शिक्षकों के लिए सारी सुविधाएं वगैरह दिए जाने के लिए एक राष्ट्रीय वेतन नीति बनाई जाये ।

श्री एल०पी० साही : महोदया, दो बातें इसमें निहित हैं । शिक्षक संघ ने कहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इम्प्लाईज को जो डीएरनेस एलाउंस मिलता है वह शिक्षकों को भी मिले . . .

श्री सभापति : वे चट्टोपाध्याय कमीशन के बारे में कह रहे हैं । चिट्ठी जो उन्होंने लिखी थी ।

श्री एल० पी० साही : चिट्ठी जो उन्होंने लिखी थी और चट्टोपाध्याय कमीशन की रिपोर्ट दाखिल होने के बाद जो सरकार ने कदम उठाया है वह मैं बताना चाहता हूं . . .

श्री राम नरेश यादव : सरकार इससे सहमत है या नही सहमत है . . . **(व्यवधान)**

श्री एल० पी० साही : चट्टोपाध्याय कमीशन ने शिक्षकों को . . . **(व्यवधान)**

श्री सभापति : इनका सिर्फ यह पूछना है कि आप इस बात से सहमत हैं या नहीं कि एक सा महंगाई भत्ता हो, इनका स्केल वगैरह एक हो ।

श्री राम नरेश यादव : आवासीय नीति और दूसरे भत्तों पर भी हो । केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के बराबर महंगाई भत्ता हो । राष्ट्रीय शिक्षक आयोग द्वारा चिकित्सा सुविधाओं, गृह निर्माण के लिए अग्रिम राशि देने के बारे में . . . **(व्यवधान)** अनुशंसाएं की गयी थी, इस बारे में आप सहमत हैं कि नहीं ।

श्री एल० पी० साही : चूंकि दोनों प्रश्न एक साथ लगे हुए हैं इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि जहां तक केन्द्रीय विद्यालयों का सवाल है, मेडिकल सुविधा इनको वही है जैसी सेंट्रल गवर्नमेंट इम्प्लायीज को है । उनको रीइम्बर्समेंट होता है । जहां तक सेकेण्डरी टीचर्स को सौ रुपये या डेढ़ सौ रुपये देने का सवाल है तो वह भी हमने मान लिया है । फोर्थ पे रिविजन कमीशन ने जो रिकमेंडेशंस की थी—टीचर्स के लिए अलग से रिकमेंडशन नहीं की थीं—उसमें उन्होंने टीचर्स को दूसरे गवर्नमेंट इम्प्लायीज के बराबर पे स्केल मानकर रिकमेंडेशंस की थी । तो उन्होंने जो रिकमेंडेशन किया था उससे हमने ज्यादा देने का निश्चय किया था ।

श्री सभापति : उनका सवाल है कि उनको आप केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के बराबर महंगाई भत्ता देने पर विचार कर रहे हैं क्या ? उन्होंने यह पूछा है इस विषय पर आप बताइये ।

श्री एल० पी० साही : अभी उस पर विचार नहीं हो रहा है चूंकि यह कई राज्य सरकारों से कन्सर्न्ड है और राज्य सरकारों का कहना है . . . **(व्यवधान)**

श्री सभापति : अपने कर्मचारियों को क्या आप केन्द्रीय भत्ता देने को तेयार हैं या सोच रहे हैं ?

श्री एल० पी० साही : अपने कर्मचारियों को तो देते ही हैं । वे तो दूसरों के बारे में पूछ रहे हैं । राज्य सरकारों के बारे में पूछ रहे हैं ।

श्री सभापति : केन्द्रीय शासन के जो कर्मचारी शिक्षक के रूप में काम कर रहे हैं उन सबको केन्द्रीय कर्मचारियों के अनुरूप आप बराबर भत्ता दे र हैं ? एम आई राइट ?

श्री एल पी० साही : जी हां, देते हैं ।

श्री राम नरेश यादव : ऐसा नहीं है । मान्यवर मैं इसलिए कह रहा हूं कि सरकार जानबूझकर सारी समस्याओं . . .

श्री सभापति : आप प्रश्न कीजिए।

श्री राम नरेश यादव : मैं प्रश्न कर रहा हूं। एक तरफ प्राइमरी शिक्षकों में गणात्मक परिवर्तन लाने का...

श्री सभापति : आप प्रश्न कीजिए :

श्री राम नरेश यादव : लेकिन उसके बाद भी जो माननीय मंत्री जी ने कहा कि केन्द्रीय सरकार के बराबर मिल रहा है, यह बात बिल्कुल नहीं है। यह नहीं मिल रहा है।

श्री सभापति : स्वास्थ्य सुविधा मिल रही है।

श्री राम नरेश यादव : स्वास्थ्य सुविधा या कोई भी सुविधा केन्द्रीय सरकार के बराबर प्राइमरी स्कूल के शिक्षकों को नहीं मिल रही है। अनशंसाओं के बारे में केवल आपने... । **(व्यवधान)**

श्री सभापति : आप बता सकते हैं तो बताइये।

श्री एल० पी० साही : मैं बता रहा हूं। प्राइमरी स्कूल के शिक्षक ज्यादातार तो राज्य सरकारों के सेक्टर में हैं। हमारे पास प्राइमरी स्कूल के शिक्षक तो वही हैं जो केन्द्रीय... **(व्यवधान)** जो प्रांतीय सरकार के हैं। हमारे पास प्राइमरी स्कूल के शिक्षक वही हैं जो केन्द्रीय विद्यालयों में इम्प्लायड हैं और उनको तो हम यह सुविधा दे ही रहे हैं। जहां तक दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन का सवाल है, दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन में भी हमने जो पे-स्केल लागू किया है, यूनियन टेरिट्रीज़ में वह सब लागू हो गया है।

अब राज्य सरकारों में जो प्राइमरी शिक्षक हैं, उनको कद्रीय सरकार के भत्ते आदि की सुविधाएं नहीं हैं। वह तो शिक्षा नीति राष्ट्रीय स्तर पर तय करती है। तो क्या इसी आधार पर एक वेतन नीति शिक्षकों की सारी स्टेटस की और उनसे संबंधित और जो सारी सुविधायें हैं, उनके बारे में कोई निर्णय लेगी या कोई नीति अपनायेगी ? अगर नहीं अपनाती है तो क्या उचित धनराशि की व्यवस्था करेगी ताकि राज्य सरकार उस दिशा में कदम उठा सके ?

श्री सभापति : धनराशि के बारे में यादव ने पूछा था, वह उसका जवाब दे चुके हैं। आप जानते हैं कि केन्द्र राज्य को मजबूर तो नहीं कर सकता।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : मान्यवर, शिक्षकों ने 14–15 नवम्बर, को दिल्ली में रैली भी की और उसके बाद जबरदस्त यहां पर धरना भी किया। उनकी मांगो का मुख्य आधार चटटोपाध्याय कमीशन था., जिसकी चर्चा अभी राम नरेश जी ने की, जिसने अपनी रिपोर्ट 25 मार्च 1985 को सरकार के पास भेज दी थी और तब श्री के० सी० पंत भारत सरकार में मंत्री थे।

मैं प्रश्न यह पूछना चाहता हूं कि चटटोपाध्याय कमीशन की जो सिफारिशें थीं, उनमें कुछ यह भी थीं, जैसे राष्ट्रीय वेतनमान, सेवा शर्तों में सुधार, उनके अवकाश प्राप्त करने की आयु को 60 साल की जगह 65 साल का प्रावधान करना और चिकित्सा भत्ते के लिए उनकी सिफारिश थी कि वेतन का 7.5 प्रतिशत उनको देना। मेरा प्रश्न यह है कि जो मुख्य-मुख्य मांगों के लिए उन्होंने धरना दिया और रैली की और शायद प्रतिवेदन भी भेंट किया इन सिफारिशों को लागू करने के लिए, तो उस पर आप क्या कार्यवाही कर रहे हैं ?

इतिहास और आध्यात्म की पूर्ण शिक्षा दी जाए, उस संदर्भ में क्या कोई एक पालिसी बनी हैं वे कितनी जल्दी सभी स्कूलों में पहुंच जाती हैं या सभी राज्य सरकारें

श्री एल० पी० साही: मान्यवर, इसको मुझे जरा एक्सप्लेन करने दिया जाए। जहां तक एक रनिंग स्केल के लागू करने का सवाल है, वह चटटोपाध्याय कमीशन के ही दूसरे रेकोमेंडेशन से कंट्राडिक्ट कर जाता है। रनिंग स्केल जब एक बार लागू होगा, तो इंसेंटिव फार गुड वर्क उसमें खत्म हो जाता है, ऐसा हम लोग मानते हैं।

इसलिए हमने जो स्केल लागू किया है, वह तीन स्केल लागू किये हैं और तीनों में चूंकि चट्टोपाध्याय कमीशन ने सिर्फ वेतन बढ़ाने का एक इलस्ट्रेटिव एक्जामपल नहीं दिया था, बल्कि शिक्षकों को अकाउंटेबिलटी और क्या दायित्व हो, कैसे वह आगे हो, इसको भी बताया था। तो हमने उसमें हर स्केल में एफिशेंसी बार इंट्रोड्यूस किया है जिसमें डी० पी० सी० के द्वारा उनका प्रोमोशन होगा। इस तरह उनकी अकाउंटेबिलटी आती है और रनिंग स्केल के खिलाफ यह पड़ता है। इसलिए रनिंग स्केल की बात को सरकार ने नहीं माना है।

जहां तक मेडिकल फेसिलिटीज का जिक्र हुआ है, मेडिकल फेसिलिटीज तो केंद्रीय विद्यालय में मिलती ही है, लेकिन दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन या दूसरी यूनियन टेरिट्रीज में जो मेडिकल फेसिलिटीज का सवाल है, वह अभी विचाराधीन है और उसमें शीघ्र ही कोई कदम उठाया जाएगा।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय: मान्यवर, उन्होंने प्रतिवेदन में सेवा निवृत्ति के लिए 65 साल की मांग की है, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जजेज 65 साल की आयु में सेवा निवृत्त होते हैं, उसी तरीके से प्राइमरी शिक्षकों ने मांग की है कि हमारी सेवा निवृत्ति होने की आयु 65 वर्ष की जाए, इसके संबंध में सरकार क्या निर्णय ले रही है?

श्री एल० पी० साही: मान्यवर, इसके संबंध में राज्य सरकारों का कहना है कि वह इस तरह का जब कोई फैसला लेंगे, तो उनके दूसरे इम्पलायीज भी इसी तरह की मांग करेंगे। इसलिए उन्होंने इसमें अपनी असमर्थता बातचीत में जाहिर की है।

दूसरी चीज, सेंट्रल स्केल पर डियरनैस अलौंस प्राइमरी स्कूल के शिक्षकों को मिले, इसमें भी राज्य सरकारों का कहना है कि अगर हम शिक्षकों को देंगे, तो हमें दूसरों को भी वैसे ही देना पड़ेगा इसलिए इसमें वह अभी जरा रुके हुए हैं।

डा० रत्नाकर पाण्डेय: मान्यवर, सभापति जी, चटटोपाध्याय आयोग से मैं भी संबद्ध रहा हूं और शिक्षकों को जब वेतनमान देने का या अन्य सुविधाये देने का प्रश्न आता है तो केंद्र सरकार स्टेट सब्जेक्ट कह करके उसको राज्यों पर टाल देती है। लाखों शिक्षक प्राइमरी शिक्षा और प्राथमिक शिक्षा में हैं और करोड़ों छात्र उसमें अध्ययन करते है और अभी पिछले बजट सत्र में 265 करोड़ रुपये शिक्षा के क्षेत्र में आवंटित थे। उसकी जगह नई शिक्षा नीति में 800 करोड़ रुपया आवंटित किया गया है। इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि अध्यायकों के लिए तो मंत्रालय बहुत कुछ कर रहा है, छात्रों को दोपहर का खाना दिए जाने की बात चर्चा में आई है, अखबारों में पढ़ने में आई है और देश में अधिकांश निर्धन छात्र प्राइमरी पाठशाला में पढ़ते हैं, उनकी संख्या बहुतायत में है, तो छात्रों के लिए एक समान वस्त्र पूरे देश में हों यानी छात्रों का एक अपना नेशनल ड्रैस हो प्राइमरी एजुकेशन में, उन्हें पूर्ण चिकित्सा की सुविधा मिले और दोपहर का भोजन उन्हें मिले इसके लिए केन्द्रीय स्तर पर क्या कोई योजना बनाई जा रही है और उसका कार्यान्वयन होना है तो वह कब तक होगा? साथ ही बराबर यह बात उठती है कि हमारा कोर्स जो है उसमें इतिहास को इस ढंग से पढ़ाया जाए...

श्री सभापति: आप सवाल पूछिए, पूरा पिटारा नहीं खोलिए। आप प्रश्न पर ही रहिए।

डा० रत्नाकर पाण्डेय: शिक्षक जो छात्रों को पढ़ाए उसमें भारतीय संस्कृति

इतिहास और आध्यात्म की पूर्ण शिक्षा दी जाए, उस संदर्भ में क्या कोई एक पालिसी पूरे देश पर लागू करने की योजना सरकार ने बना रखी है ?

श्री सभापति : आपका यह जो सप्लीमेंट्री है यह इसमें से नहीं उठता है। यह मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, आप जो संबंधित है वह सप्लीमेंट्री ही पूछिए।

डा० रत्नाकर पाण्डेय : मैं संबंधित ही पूछ रहा हूं।

श्री सभापति : यह संबंधित नहीं है।

डा० रत्नाकर पाण्डेय : चट्टोपाध्याय आयोग ने छात्रों के लिए जो सिफारिशें की हैं उसी संदर्भ में मेरा प्रश्न है कि क्या छात्रों को दोपहर का भोजन दिया जायेगा ?

श्री सभापति : वह तो पूछ लिया, वह आपका ठीक सवाल है।

डा० रत्नाकर पाण्डेय : क्या कोई ऐसा नेशनल कोर्स बना रहे जो राष्ट्रीय स्तर पर एकता के लिए अनिवार्य हो प्राइमरी एजुकेशन में इस तरह की सिफारिश क्या चट्टोपाध्याय आयोग ने की है ? अगर की है तो उस पर क्या कार्यवाही कर रहे हैं ?

श्री एल० पी० साही : जहां तक विद्यार्थियों के लिए भोजन और कपड़े का संबंध है तो यह सवाल तो शिक्षकों का था लेकिन मैं यही कहूंगा कि अगर ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा हमें भी लगेगा कि सभी विद्यार्थियों के लिए एक ड्रैस रहें और सभी को भोजन मिले। जहां तक दूसरे प्रश्न का संबंध है कि पढ़ाई के लिए इतिहास का कोर्स ऐसा डिजाइन किया जाए जिससे राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बल मिले तो इस दिशा में काफी काम हुआ है। कोर्सेज री-डिजाइन हो रहे हैं, किताब नई लिखी गई हैं। अब सवाल यह है कि जो नई किताबें बनी हैं वे कितनी जल्दी सभी स्कूलों में पहुंच जाती हैं या सभी राज्य सरकारें उनको अपना लेती हैं इसका प्रश्न है, नहीं तो उस दिशा में काफी काम हुआ है।

श्री चिमन भाई मेहता : सर, मंत्री जी ने बताया कि रनिंग पे-स्केल इसलिए नहीं दिया जा रहा है कि उससे इंसटिव कम हो जाता है। अगर एक सिद्धांत बनाया है तो क्या गवर्नमेंट की और भी सर्विसेज में इंसेटिव नहीं दिए जाते और रनिंग पे-स्केल भी चलता है ? अगर दोनों दूसरी सर्विसेज में चलते हैं तो इधर दोनों को अलग-अलग हमने क्यों कर दिया।

श्री सभापति : वह एफीशिएंसी बार की बात कर रहे हैं।

श्री चिमन भाई मेहता : हां, वही तो।

श्री सभापति : एफीशिएंसी बार तो करीब-करीब सब सर्विसेज में है।

श्री चिमनभाई मेहता : नहीं, अगर है तो वही मैं पूछ रहा हूं। तो इसमें रनिंग पे-स्केल आपने क्यों निकाल दिया ?

श्री सभापति : वह चेंज चाहते थे कि एफीशिएंसी बार हटा करके विदाउट एफीशिएंसी बार रनिंग पे-स्केल हो। अब जब यह प्रश्न इन्होंने किया है कि एफीशिएंसी बार रहने से इंसेटिव रहता है...।

श्री चिमन भाई मेहता : नहीं, रनिंग पे-स्केल ही निकाल दिया है। That is the answer they have given, we have not adopted the running pay-scale and therefore I am asking this question.

कि रनिंग पे-स्केल क्यों नहीं आप दाखिल करते जबकि और जगह दाखिल होता है ?

श्री एल० पी० साही : वही है जैसे फोथ पे रिवीजन कमीशन ने कहा था कि 1200 से 2040 तक बीच में एक

एफीशिएंसी बार और दूसरे के लिए 1400 से 2600 तक हो और अभी हम लोगों ने जो प्रेसक्राइब करके दिया है उसमें 1200 से 2900 तक का तीन ग्रेड दिया है ।

श्री सभापति : 2600 था 2900 कर दिया ।

श्री एल० पी० साही : वहां पर 2600 था उसको हमने बढ़ाकर 2900 तक किया । और 1200 उन्होंने जो फोर्थ पे-रिवीजन कमीशन में कहा था वह 1200 है । लेकिन यही हुआ है कि उनमें एफीसियेन्सी लाने के लिए एफीसियेन्सी बार कर दिया है क्योंकि कहीं ऐसा न हो कि बिना काम किए हुए या बिना कुछ किए हुए वहां पहुंच जाय । सिर्फ इतना ही रोका है ।

श्री चिमनभाई मेहता : सर, मेरा सवाल रनिंग स्केल से था ।... (व्यवधान)...

श्री सभापति : वह जवाब तो हो गया ।

SHRI MOHD. KHALEELUR RAHMAN: I would like to know whether States have been given special grants to meet the financial burden likely to come as a result of the implementation of the Chattopadhyaya Commission's Report.

श्री एल० पी० साही : अभी ऐसी कोई बात सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

श्री शिव कुमार मिश्र : सभापति जी, क्या सरकार राज्य सरकारों को यह सुझाव देगी कि चूंकि अध्यापकों के वेतन बढ़ गए हैं प्राइमरी के, तो उनको जिस खंड के वह निवासी हैं जिस ब्लाक खंड के उसके अलावा ब्लाक के बाहर दूसरे खंडों में उनका स्थानांतरण किया जाएगा? क्या ऐसा कोई सुझाव सरकार देने का इरादा रखती है ?

श्री एल० पी० साही : अभी हमारे सामने ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं । लेकिन कई राज्य सरकारों ने अपने यहां इसको लागू किया है कि एक प्रखंड के लोगों को दूसरे प्रखंड में रखा जाय । यह पूर्णतया राज्य सरकार के अंदर का मामला है ।

DR. (SHRIMATI) SAROJINI MAHISHI: According to the Directive Principles of State Policy, primary education should be free and compulsory. I would like to know whether the Government has made a survey if it has been free and compulsory. In the private sector, number of primary schools, English-medium schools have come up and heavy capitation fee is charged even at the stage of admission. Why is it being charged? Primary schools run by the Government are supposed to serve the poorer people.

MR. CHAIRMAN: It does not arise out of the main question, but if the Minister likes, he can answer it.

डा० (श्रीमती) सरोजिनी महिषी : सर, मिनिस्टर साहब जवाब नहीं दे रहे ।

श्री सभापति : क्योंकि इससे उठता नहीं है ।

डा० (श्रीमती) सरोजिनी महिषी : उठता है साहब ।

श्री सभापति : आप क्वैश्चन देखें । ...(व्यवधान)...पूरी शिक्षा-नीति का सवाल थोड़े ही है कि उस पर डिस्कशन कर लेंगे ।

Next question.

Railway Line between Udhampur and Srinagar

*362. SHRI GHULAM RASOOL MATTO: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a preliminary survey for a railway line